



भारत सरकार/Government of India

दूरसंचार विभाग/Department of Telecommunications

कार्यालय अपर महानिदेशक दूरसंचार, पंजाब एलएसए/ O/o Additional Director General Telecom, Punjab LSA

सं. 5-7/पीबीएलएसए/2022/एसबीसी-चंडीगढ़

दिनांक: 26.09.2025

सेवा में,

राज्य ब्रॉडबैंड समिति के सभी सदस्यों,
यूटी चंडीगढ़।

विषय: 03.09.2025 को आयोजित संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की 6वीं एसबीसी बैठक का कार्यवृत्त

वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही के लिए 3 सितंबर 2025 को आयोजित संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए राज्य ब्रॉडबैंड समिति (एसबीसी) की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति आपके अंत में आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ संलग्न है।

अनुलग्नक: जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सहायक निदेशक (सीएचडी)

मीटिंग का विवरण

6वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक - चंडीगढ़ यूटी

दिनांक: 3 सितंबर 2025 (बुधवार) अपराह्न 03:30 बजे

अध्यक्ष: श्री मंदीप सिंह बरार, आईएस, मुख्य सचिव, चंडीगढ़ यूटी

द्वारा संयोजक: श्री अनिल कुमार रंजन, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार पंजाब एलएसए, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार।

राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक 3 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत चंडीगढ़ के उप महानिदेशक श्री अजय नेगी के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद एजेंडा मदों पर एक प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान हुए मुख्य विचार-विमर्श इस प्रकार हैं:

(I) एजेंडा बिंदु 1: 5वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति (एसबीसी) बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा:

क्र.	चर्चा बिंदु	चर्चा आयोजित	आगे की कार्रवाई
1	ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में ओवरहेड दूरसंचार लाइन का प्रावधान।	शहरी नियोजन: सीएचडी मास्टर प्लान-2031, यूटी के ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में ओवरहेड दूरसंचार लाइन की अनुमति नहीं देता है। एमसीसी: ग्रामीण सड़कों पर सीमित मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता के कारण, एक विस्तृत सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया गया। मुख्य वास्तुकार, यूटी (सीएयूटी) के परामर्श से भूमिगत सामान्य नलिकाओं के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।	अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि भूमिगत दूरसंचार लाइन की सुविधा में तेजी लाई जाए तथा इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। [कार्रवाई: इंजीनियरिंग विभाग और एमसीसी द्वारा]
2	सामान्य वाहिनी के निर्माण के लिए संयुक्त प्रस्ताव	दूरसंचार विभाग: कॉमन डक्ट के लिए सीओआई का प्रस्ताव आईटी विभाग के साथ साझा किया गया है।	अध्यक्ष ने आयुक्त, एमसीसी और सचिव (आईटी) को सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाने और प्रस्ताव की विस्तार से जांच करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: एमसीसी, एसआईटी, डीओटी, सीओआई]

3	दूरसंचार टावरों का साझाकरण	सीओआई: ऑपरेटर आमतौर पर टावरों को साझा करते हैं, कुछ स्थानों को छोड़कर जहां विभिन्न कारणों से साझा करना संभव नहीं है। डीआईपीए: इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं (आईपी) द्वारा स्थापित टावर सभी ऑपरेटरों के लिए साझा करने के लिए खुले हैं। हालाँकि, आरजेआईओ के टावर ढांचे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे साझा करने का समर्थन नहीं करते हैं। बीएसएनएल: वे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं (आईपी) के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, आईपी ने कई बाधाओं का हवाला दिया है—जैसे तकनीकी सीमाएँ (संरचनात्मक स्थिरता), स्वामित्व संबंधी मुद्दे और विक्रेता-संबंधी चुनौतियाँ—जो कुछ स्थानों पर टावर साझा करने में बाधा डालती हैं।	अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि इन मुद्दों को शीघ्र हल किया जाए, तथा इस बात पर बल दिया कि बुनियादी ढांचे की सीमाओं को दूर करने तथा संघ राज्य क्षेत्र में ग्रे क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टावरों को साझा किया जाना चाहिए। [कार्रवाई: सभी आईपी, टीएसपी, सीओआई, डीआईपीए और दूरसंचार विभाग द्वारा]
4	आरओडब्ल्यू पोर्टल पर निजी संपत्ति फॉर्म को सक्रिय करना, इस उद्देश्य के लिए संरचनात्मक सुरक्षा सहित संपदा नियमों के अनुपालन के अधीन है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी आवासीय भवनों पर कोई स्थापना स्वीकृत न हो।	एनआईसी: आरओडब्ल्यू पोर्टल पर निजी वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए फॉर्म सक्रिय कर दिया गया है। एडीसी: निजी आवासीय भवनों के लिए कभी कोई अनुमति/अनुमोदन नहीं दिया गया।	आइटम बंद
5	ऐसे मामलों में वार्षिक किराये की वापसी का प्रावधान जहां सार्वजनिक विरोध या अन्य वैध न्यायोचित कारणों से टावर स्थापना का कार्य नहीं किया जाता है।	एमसीसी: दूरसंचार कम्पनियों द्वारा नगर निगम के पास जमा किया गया किराया या धनराशि, नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन तथा सभी अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने के अधीन, वापस की जा सकती है या किसी अन्य मोबाइल टावर स्थल के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है। दूरसंचार विभाग: वर्तमान में, किराए की वापसी या समायोजन के लिए कोई मानक	अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि एक एसओपी तैयार किया जाए और उसे टीएसपी के साथ साझा किया जाए। [कार्रवाई: एमसीसी]

		संचालन प्रक्रिया (SOP) नहीं है। अतः अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र एक SOP जारी की जाए।	
6	RoW नियम 2024 अपनाने का आदेश जारी करना	आईटी विभाग: गोद लेने का आदेश दिनांक 29.05.2025 के पत्र द्वारा जारी किया गया था।	आइटम बंद
7	एयरटेल के पीयू और पीईसी ग्रे एरिया	पीयू: सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, तथा चर्चा, आगे के विश्लेषण और अनुमोदन के लिए आगामी सप्ताह में समिति की बैठक निर्धारित है। पीईसी: आवेदन RoW पोर्टल पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा मुख्य वास्तुकार के कार्यालय में विचारार्थ लंबित है।	अध्यक्ष ने एडीसी को निर्देश दिया कि वे आगामी सप्ताह के अंत तक कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। [कार्यवाही: एडीसी]
8	एयरटेल का ग्रे एरिया	एयरटेल: ड्राइव टेस्ट के बाद, ग्रे एरिया की पहचान और अनुकूलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में सिग्नल कवरेज में सुधार हुआ। ड्राइव टेस्ट के परिणाम बताते हैं कि अनुकूलन के बाद कवरेज में कोई कमी नहीं देखी गई। दूरसंचार विभाग: इस क्षेत्र में एक स्थल की योजना बना ली गई है और उसे मंजूरी दे दी गई है; हालांकि, स्थानीय जनता के विरोध के कारण इसकी स्थापना में देरी हो गई है।	1. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि ग्रे क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सरकारी भवनों के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए। 2. अध्यक्ष ने एडीसी को उचित स्थलों की शीघ्र पहचान करने में सहायता करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: सभी आईपी, एडीसी, डीओटी द्वारा]
9	ग्रे एरिया कवरेज के लिए बीएसएनएल की समयरेखा	बीएसएनएल: ये उच्च किराये वाली साइटें हैं, और यह मामला पहले ही आईपी विक्रेताओं और मुख्यालय के समक्ष उठाया जा चुका है। बीएसएनएल इस मामले को आगे बढ़ा रहा है।	1. अध्यक्ष ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि वह संबंधित अवसंरचना प्रदाताओं के विवरण के साथ सभी साइटों की एक व्यापक सूची डीआईपीए और दूरसंचार विभाग को शीघ्र कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराए। 2. अध्यक्ष ने डीआईपीए और दूरसंचार विभाग को बुनियादी ढांचे के बंटवारे

			के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: बीएसएनएल, डीआईपीए, सीओआई और दूरसंचार विभाग]
10	VIL के ग्रे स्थान	उप महानिदेशक (सीएचडी) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि वीआईएल ने नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए तीन स्थानों का प्रस्ताव रखा है। इनमें से, पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में इंडस टावर्स द्वारा टावर लगाने पर विचार किया जा रहा है। शेष दो स्थानों (कला ग्राम और जीएमएसएच सेक्टर-16) के लिए, वीआईएल वर्तमान में एक बुनियादी ढाँचा प्रदाता के साथ समन्वय करके स्थल व्यवहार्यता का आकलन कर रहा है। पी.ई.सी. के निकट ग्रे क्षेत्र को पी.जी.आई. के नए ओ.पी.डी. भवन में बी.टी.एस. स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया गया है।	अध्यक्ष ने वीआईएल और डीआईपीए को मामले का शीघ्र समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ग्रे एरिया कवरेज संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान किया जाए। [कार्रवाई: दूरसंचार विभाग, वीआईएल, डीआईपीए]
11	सभी ऑपरेटरों से ट्रार्ड रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया	• एयरटेल: चंडीगढ़ में सभी वॉयस और डेटा QoS पैरामीटर सीमा के भीतर हैं, जो संतोषजनक नेटवर्क प्रदर्शन को दर्शाता है। कुल मिलाकर ट्राइसिटी कवरेज अच्छा है और नियमित ड्राइव टेस्ट और ऑप्टिमाइज़ेशन के माध्यम से इसमें सुधार हो रहा है। • बीएसएनएल: ड्राइव टेस्ट के दौरान, 4G साइट्स इंस्टॉल नहीं की गईं, जिसके परिणामस्वरूप MOS (स्पीच क्वालिटी के लिए मीन ओपिनियन स्कोर) खराब रहा। हालाँकि, अब पर्याप्त 4G साइट्स स्थापित हो चुकी हैं, और डाउनलोड और अपलोड स्पीड के साथ-साथ MOS में भी सुधार होने की उम्मीद है। • RJIO ने सभी वॉयस QoS मानकों को सर्वोच्च कॉल सेटअप सफलता दर (99.92%) और 99.84% हैंडओवर सफलता के साथ पूरा किया। आंकड़ों के अनुसार, इसकी डाउनलोड स्पीड सबसे अच्छी, अपलोड स्पीड दूसरी सबसे अच्छी और पिंग रिसर्पॉन्स सबसे अच्छी रही। • ड्राइव परीक्षण के अनुसार वीआईएल ने क्यूओएस मापदंडों के मानक को पूरा	बैठक में विभिन्न प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। [कार्रवाई: दूरसंचार विभाग, सभी दूरसंचार सेवाप्रदाता, सीओआई और डीआईपीए]

		कर लिया है, अब वीआई द्वारा कोई और कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	
12	हरित ऊर्जा खुली पहुँच - GEOA	सीपीडीएल: एनटीपीसी का एक मामला अगस्त में लागू किया गया था, और एक अन्य मामला अभी प्रक्रिया में है। चूँकि वर्तमान में मामलों की संख्या कम है, इसलिए प्रक्रिया मैनुअल रूप से संचालित की जा रही है। हालाँकि, जैसे-जैसे मामलों की संख्या बढ़ेगी, स्वचालित प्रणाली में स्थानांतरण की योजना बनाई जा रही है, और इस परिवर्तन पर काम शुरू हो चुका है। सीओआई: क्षेत्र के सभी डिस्कॉम के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना जारी की जा सकती है।	अध्यक्ष ने सीपीडीएल को निर्देश दिया कि वह संघ राज्य क्षेत्र में जीईओए प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करे तथा अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। [कार्यवाही द्वारा: सीपीडीएल]
13	दूरसंचार चोरी के मामले: 1. 2023 तक 6 मामले लंबित रहेंगे। 2. वित्त वर्ष 2024-25 में 11 नए मामले (8 डीडीआर; 3 ऑनलाइन) रिपोर्ट किए गए।	सीएचडी पुलिस: कुल नौ मामले एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से दो मामले लंबित हैं। दर्ज एफआईआर में से तीन मामले सफलतापूर्वक सुलझा लिए गए हैं और आरोपियों को पकड़ लिया गया है।	अध्यक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस को सभी डीडीआर को एफआईआर में बदलने और सभी लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने सीएचडी पुलिस को तीनों सुलझाए गए मामलों का विवरण दूरसंचार विभाग के साथ साझा करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: सीएचडी पुलिस]
14	एनबीएम से आरओडब्ल्यू निष्पादन समय का पालन न करने पर दंड संबंधी धाराओं को शामिल करने के लिए एमसी सीएचडी के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण	दूरसंचार विभाग: दिनांक 08.07.2025 के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है।	[आइटम बंद]
15	कॉल बिफोर यू डिग ऐप: • सीपीडीएल को शामिल करना	• सीपीडीएल: सीपीडीएल ने सीबीयूडी ऐप पर काम करना शुरू कर दिया है और सभी एल3, एल4 उपयोगकर्ताओं का निर्माण पूरा कर लिया है	अध्यक्ष ने भूमिगत परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश में सभी उत्खनन-संबंधी कार्यों के लिए सीबीयूडी ऐप के

	• CBUd ऐप के संबंध में अधिदेश	• यह शासनादेश दिनांक 29.05.2025 की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया है। उप महानिदेशक (सीएचडी) ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीबीयूडी पूछताछ के पहले और दूसरे तिमाही के तिमाही लक्ष्यों को प्राप्त करने में एडीसी के प्रयासों की सराहना की। हालाँकि, मानसून के मौसम के कारण, विकास कार्य फिलहाल रुके हुए हैं, इसलिए चालू तिमाही के दौरान सीबीयूडी के बारे में पूछताछ कम रही।	अनिवार्य उपयोग का निर्देश दिया।
16	मौजूदा टावर नियमितीकरण के लिए अधिकृत और अनधिकृत टावरों की सूची प्राप्त की जाएगी।	शहरी नियोजन : साइट रिकॉर्ड की अंतिम स्वीकृति संपदा कार्यालय, यूटी, चंडीगढ़ के पास उपलब्ध होगी। हालाँकि, 168 मामलों को संपदा कार्यालय को अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया है। एमसीसी : एनआईसी से दूरसंचार टावरों की सर्वेक्षण सूची साझा करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस सूची के आधार पर, अनधिकृत या अवैध टावरों की पहचान की जा सकती है और लागू नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने अध्यक्ष को सूचित किया कि दी गई 151 जीबीटी अनुमतियों में से 141 स्थापित हो चुकी हैं। एनआईसी: सभी सर्वेक्षण किए गए टावरों की सूची सभी संबंधित विभागों के साथ साझा कर दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने अध्यक्ष महोदय को बताया कि आंकड़ों के अनुसार, यूटी सीएचडी में कुल 77 अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं। डीआईपीए: प्रस्तुत किया गया कि लगभग 262 साइटें नियमितीकरण के लिए लंबित हैं। COAI: सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अभी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द सूची साझा करेंगे।	अध्यक्ष ने सीओएआई और डीआईपीए को निर्देश दिया कि वे सभी अधिकृत टावरों की विस्तृत सूची यूटी प्रशासन के साथ साझा करें, जिसकी एक प्रति दूरसंचार विभाग को भी भेजी जाए। [कार्रवाई: COAI, DIPA] अध्यक्ष ने एडीसी को सभी संबंधित विभागों और सुविधा प्रदाताओं के साथ बैठक आयोजित कर अनाधिकृत टावरों की पहचान करने तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [कार्रवाई: एडीसी, आईटी, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, एमसीसी, एस्टेट, सभी सुविधा प्रदाता]
17	स्मार्ट मीटरिंग और समग्र बिलिंग योजना	समग्र बिलिंग: इंजीनियरिंग विभाग ने अध्यक्ष को बताया कि सीपीडीएल ने समग्र बिलिंग लागू करने पर सहमति व्यक्त की है और अब वह ऑपरेटर-वार स्टेपल्ड समग्र बिल जारी करेगा।	अध्यक्ष ने इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। [कार्यवाही द्वारा: सीपीडीएल]

		स्मार्ट मीटरिंग: इंजीनियरिंग विभाग ने अध्यक्ष को बताया कि सीपीडीएल का अनुमान है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में स्मार्ट मीटर लगाने में लगभग दो साल लगेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है और स्मार्ट मीटर कनेक्टिविटी दिसंबर 2025 तक होने की उम्मीद है। बड़े उपभोक्ताओं को मार्च 2026 तक कनेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि छोटे उपभोक्ताओं को कनेक्ट करने में अतिरिक्त समय लगेगा।	
18	समीक्षा के लिए जांच करना सामान्य डक्ट और पोस्ट पर यूटी नीति से संबंधित लागू दरों की जानकारी।	एमसीसी: मामला अभी प्रक्रियाधीन है और सामान्य डक्ट तथा संबद्ध बुनियादी ढांचे से संबंधित नीति निर्माण तथा दर समीक्षा के लिए इसकी जांच की जा रही है।	अध्यक्ष ने एमसीसी को 15 दिनों के भीतर सामान्य डक्ट के लिए दरें अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: एमसीसी]

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सभी प्रतिभागियों की सूची

विभाग/संगठन	प्रतिभागियों का नाम	पद का नाम
चंडीगढ़ यूटी	श्री मंदीप सिंह बराड़	प्रमुख शासन सचिव
	श्री अमित कुमार	आयुक्त (सीएमसी)
	श्री प्रदीप कुमार	विशेष आयुक्त (सीएमसी)
	श्री हरि कल्लिकट	सचिव (आईटी)
	श्री अमनदीप सिंह भट्टी	एडीसी
	श्री नितीश सिंगला	निदेशक (आईटी)
	श्री सी.बी. ओझा	मुख्य अभियंता (इंजीनियरिंग विभाग)
	श्री रमेश कुमार गुप्ता	एसआईओ (एनआईसी)
	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	एसई (बी एंड आर) (सीएमसी)
	सुश्री मंदीप	वरिष्ठ नगर नियोजक (DoUP)
	श्री अनुराग बिश्रोई	ईई (आर-3) (सीएमसी)
	श्री रवि कुमार	कार्यकारी अभियंता , सीपी-I (इंजीनियरिंग विभाग)
	श्री नवदीप सोनी	ईओ (एस्टेट ऑफिस) के लिए एसडीओ (बी)
	श्री रोहित कुमार	निरीक्षक (सीएचडी पुलिस)
	श्री प्रमोद मिश्रा	वीपी (सीपीडीएल)
	श्री ऐश्वर्या सारस्वत	प्रबंधक (सीपीडीएल)
पंजाब एलएसए, दूरसंचार विभाग	श्री अनिल कुमार रंजन	अतिरिक्त डीजीटी
	श्री बी.एम. सेतिया	डीडीजी (आर)
	श्री अजय नेगी	डीडीजी (सीएचडी)
	श्री सुनील भाट	एडी (सीएचडी)
बीएसएनएल	श्री एस.के. चोपड़ा	पीजीएम (एनडब्ल्यू-सीएम)
	श्री पुरुषोत्तम लाल	डीजीएम
	श्री बलविंदर कुमार	एजीएम
बीबीएनएल	श्री जितेंद्र सेतिया	पीजीएम (बीएन)
	श्री उपेन्द्र पाठक	डीजीएम (बीएन)
COAI (ऑनलाइन)	श्री धनंजय गावंडे	निदेशक
	श्री दीपक गुप्ता	प्रबंधक
DIPA (ऑनलाइन)	श्री ग्रीश कुमार त्यागी	महाप्रबंधक



भारत सरकार/Government of India

दूरसंचार विभाग/Department of Telecommunications

कार्यालय अपर महानिदेशक दूरसंचार, पंजाब एलएसए/ O/o Additional Director General Telecom, Punjab LSA

No. 5-7/PBLSA/2022/SBC-Chandigarh

Date: 26.09.2025

To,

All Members of the State Broadband Committee,
UT Chandigarh.

Subject: Minutes of the 6th SBC Meeting of UT Chandigarh held on 03.09.2025

The minutes of the 6th meeting of the State Broadband Committee (SBC) for UT Chandigarh, held on 3rd September 2025 for the second quarter of FY 2025–26, have been approved by the competent authority. A copy of the approved minutes is enclosed herewith for necessary action at your end.

Encl.: As above

Assistant Director (CHD)

Minutes of the Meeting

6th State Broadband Committee Meeting – Chandigarh UT

Date: 03rd September 2025 (Wednesday) at 03:30 PM

Chairperson: Shri Mandip Singh Brar, IAS, Chief Secretary, Chandigarh UT

Convened By: Sh. Anil Kumar Ranjan, Addl. DG Telecom Punjab LSA,
Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India.

State Broadband Committee Meeting was held in Chandigarh on 03rd September 2025 under the chairmanship of the Chief Secretary, Chandigarh. The meeting commenced with a welcome address by Shri Ajay Negi, Deputy Director General, Chandigarh, followed by a presentation on the agenda items. The key deliberations held during the meeting are as follows:

(I) Agenda Point 1: Review of Minutes of the 5th State Broadband Committee (SBC) Meeting:

Sr No	Discussion Point	Discussion Held	Further Course of Action
1	Provision of Overhead Telecommunication Line in Rural and Peripheral Areas of UT.	Urban Planning: CHD Master Plan-2031 does not allow overhead telecommunication line in Rural and Peripheral areas of UT. MCC: Due to limited Right of Way (RoW) availability along rural roads, it was suggested that a detailed survey be conducted. The feasibility of implementing underground common ducts may be explored in consultation with the Chief Architect, UT (CAUT).	The Chair has directed that the facilitation of the underground telecommunication line be accelerated and executed promptly. [Action by: Engg. Deptt. and MCC]
2	Joint Proposal for creation of common duct	DoT: The COAI's proposal for common duct has been shared with IT Deptt.	The Chair directed the Commissioner, MCC, and Secretary (IT) to convene a meeting with all stakeholders and examine the proposal in detail. [Action by: MCC, SIT, DoT, COAI]
3	Sharing of Telecom Towers	COAI: The operators generally share towers as a common practice, except at	The Chair directed that these issues be resolved

		certain locations where sharing is not feasible for various reasons. DIPA: Towers installed by Infrastructure Providers (IP) are open for sharing by all operators. However, the tower structures of RJIO are designed in a manner that does not support sharing. BSNL: They are actively pursuing the matter with the concerned Infrastructure Providers (IPs). However, the IPs have cited various constraints—such as technical limitations (structural stability), ownership issues, and vendor-related challenges—which prevent tower sharing at certain locations.	promptly, emphasizing that towers must be shared to overcome infrastructure limitations and ensure coverage of the grey areas in the UT. [Action by: All IPs, TSPs, COAI, DIPA and DoT]
4	Activation of Private Property form on the RoW Portal, subject to compliance with Estate Rules including structural safety for this purpose to ensure that no installation on private residential buildings gets approved.	NIC: The form has been activated for private commercial properties on the RoW portal. ADC: No permissions/approval for private residential buildings were ever granted.	Item Closed
5	Provision for Refund of Annual Rent in Cases where Tower Installation is not Executed due to Public Protests or other Valid Justified Reasons.	MCC: The rent or funds deposited by telecom companies with the Municipal Corporation may be refunded or adjusted against another mobile tower site, subject to the approval of the Worthy Commissioner, M.C., and completion of all requisite formalities. DoT: Currently, there is no Standard Operating Procedure (SOP) for the refund or adjustment of rent. Therefore, it is requested that an SOP be issued at the earliest.	The Chair directed that an SOP to be prepared and shared the same with the TSPs. [Action by: MCC]
6	Issuance of RoW Rules 2024 adoption order	IT Deptt.: The adoption order was issued vide letter dated 29.05.2025.	Item Closed

7	PU and PEC Grey Areas of Airtel	PU: The survey report has been submitted, and a committee meeting is scheduled in coming week for discussion, further analysis and approval. PEC: The application has been submitted for approval on the RoW portal and is pending for consideration with the office of Chief Architect.	The Chair instructed the ADC to ensure the completion of the task by the end of the coming week. [Action By: ADC]
8	Sector 15/16 Residential Area and connecting Roads - Grey Area of Airtel	Airtel: Following the drive test, grey area identification and optimization were undertaken, resulting in improved signal coverage throughout the region. The drive test results indicate that no coverage gaps were observed after the optimization. DoT: A site has been planned and approved in the area; however, its installation has been delayed due to local public protests.	1. The Chair directed that the feasibility of utilizing government buildings in the area be explored to enhance coverage in the grey areas. 2. The Chair directed the ADC to facilitate the prompt identification of appropriate sites [Action by: All IP, ADC, DoT]
9	Timeline from BSNL for grey area coverage	BSNL: These are high-rent sites, and the matter has already been taken up with IP vendors and HQ. The case is being pursued by BSNL.	1. The Chair directed BSNL to provide a comprehensive list of all sites along with the details of the respective infrastructure providers, to DIPA and DoT for expedited processing. 2. The Chair directed DIPA and DoT to resolve the infrastructure sharing issue at the earliest. [Action by: BSNL, DIPA, COAI and DoT]
10	VIL's Grey Locations	DDG (CHD) apprised the Chair that VIL has proposed three locations to enhance network coverage. Among	The Chair directed VIL and DIPA to address the matter promptly and

		these, Panjab University (PU) is being considered for tower installation by Indus Towers. For the remaining two locations (Kala Gram and GMSH Sec-16), VIL is currently assessing site feasibility in coordination with an Infrastructure Provider. The grey area near PEC has been addressed by installing a BTS at PGI's new OPD building to serve the area.	ensure that grey area coverage concerns are resolved at the earliest. [Action By: DoT, VIL, DIPA]
11	Feedback on TRAI Report from all operators	• Airtel: All voice and data QoS parameters in Chandigarh are within limits, reflecting satisfactory network performance. Overall Tricity coverage is good and improving through regular drive tests and optimization • BSNL: During the drive test, 4G sites were not installed, which resulted in poor MOS (Mean Opinion Score for speech quality). However, enough 4G sites have now been deployed, and the MOS is expected to improve accordingly along with download and upload speeds. • RJIO meeting all voice QoS benchmarks with the highest call setup success rate (99.92%) and 99.84% handover success. In data, it had the best download speed, second-best upload, and best ping response. • VIL have met the benchmark of QoS parameters as per Drive test, further no action is required by Vi.	The Chair directed that, based on feedback from various participants in the meeting revealed that there are still grey areas and coverage needs to be improved. [Action by: DoT, All TSPs, COAI and DIPA]
12	Green Energy Open Access - GEOA	CPDL: One NTPC case was implemented in August, with another case currently in the pipeline. Since the number of cases is presently low, the process is being handled manually. However, as the volume increases, migration to an automated system is planned, and work on this transition has already commenced. COAI: A notification may be issued for Green Energy Open Access to all	The Chair directed CPDL to issue the notification for the effective implementation of GEOA process in the UT and the progress report to be presented at the next meeting. [Action By: CPDL]

		the discoms in the area for its effective implementation.	
13	Telecom Theft Cases: 6 pending cases of 2023. 11 new cases (8 DDR; 3 Online) reported in FY 2024-25.	CHD Police: A total of nine cases has been registered as FIRs, with two cases pending registration. Among the registered FIRs, three cases have been successfully solved, and the accused have been apprehended.	The chair directed Chandigarh Police to convert all the DDRs into FIR and expedite all pending cases. The chair further directed CHD Police to share the details of the 3 solved cases to DoT. [Action By: CHD Police]
14	Clarification on the Proposal of MC CHD for the Inclusion of Penalty Clauses for Non-adherence to RoW Execution Time from NBM	DoT: The clarification has been provided vide letter dated 08.07.2025.	[Item Closed]
15	Call Before You Dig App: - CPDL to Onboard - Mandate regarding the CBuD App	CPDL: CPDL has on boarded on the CBuD App and has completed the creation of all L3, L4 users - The mandate has been issued vide notification dated 29.05.2025 DDG (CHD) appreciated ADC's efforts in achieving the quarterly targets for first and second quarters of CBuD enquiries for UT. However, due to the monsoon season, development works are currently on hold and hence lower inquiries on CBuD during current quarter.	The Chair directed the mandatory use of the CBuD App for all excavation-related works in the UT to safeguard the underground assets.
16	List of authorized and unauthorized towers for the existing tower regularization to be obtained.	Urban Planning: The final approval of the sites record will be available with Estate Office UT, Chandigarh. However, 168 cases have been recommended by them to Estate office for their approval for permission. MCC: NIC may be requested to share the survey list of telecom towers. Based on this list, unauthorized or illegal towers can be identified, and appropriate action may be initiated as per applicable regulations. They informed the chair that out of 151 GBT	The Chair directed COAI and DIPA to share the comprehensive list of all authorized towers with the UT Administration, with a copy marked to the DoT. [Action by: COAI, DIPA] The Chair directed the ADC to convene a meeting with all the

		permissions granted, 141 have been installed. NIC: The list of all surveyed towers has already been shared with all concerned departments. Further, they informed the chair that as per data a total of 77 permissions have been granted in the UT CHD. DIPA: Submitted that approx. 262 sites are pending for Regularization. COAI: The details are yet to receive from all TSPs. We will work it out and share the list at the earliest.	concerned departments and facility providers to identify the unauthorized towers and ensure necessary action as per law. [Action by: ADC, IT, Engg., Urban Planning, MCC, Estate, All facility providers]
17	Smart Metering and Composite Billing Scheme	Composite Billing: The Engineering Department apprised the Chair that CPDL has agreed to implement composite billing and will now be issuing operator-wise stapled composite bills. Smart Metering: The Engineering Department apprised the Chair that CPDL estimates approximately two years to complete the installation of smart meters across the Union Territory (UT). The industrial sector is being prioritized, with smart meter connectivity expected by December 2025. Large consumers are projected to be connected by March 2026, while the connection of smaller consumers will require additional time.	The Chair directed the same to be expedited [Action By: CPDL]
18	To examine for review of applicable rates related to the UT policy on common duct and posts.	MCC: The matter is currently under process and is being examined for policy formulation and rate review related to the common duct and associated infrastructure.	The Chair directed MCC to finalize the rates for common duct within 15 days. [Action By: MCC]

The Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Note: Hindi version follows.

List of All Participants

Dept/Org	Name of Participants	Designation
Chandigarh U.T.,	Sh. Mandip Singh Brar	Chief Secretary
	Sh. Amit Kumar	Commissioner (CMC)
	Sh. Pradeep Kumar	Special Commissioner (CMC)
	Sh. Hari Kallikat	Secretary (IT)
	Sh. Amandeep Singh Bhatti	ADC
	Sh. Nitish Singla	Director (IT)
	Sh. C. B. Ojha	Chief Engineer (Engineering Deptt.)
	Sh. Ramesh Kumar Gupta	SIO (NIC)
	Sh. Dharmendra Sharma	SE (B&R) (CMC)
	Ms. Mandip	Senior Town Planner (DoUP)
	Sh. Anurag Bishnoi	EE (R-3) (CMC)
	Sh. Ravi Kumar	Executive Engineer, CP-I (Engineering Deptt.)
	Sh. Navdeep Soni	SDO (B) for AEO (Estate Office)
	Sh. Rohit Kumar	Inspector (CHD Police)
	Sh. Pramod Mishra	VP (CPDL)
	Sh. Aishwary Saraswat	Manager (CPDL)
Punjab LSA, DoT	Sh. Anil Kumar Ranjan	Addl. DGT
	Sh. BM Setia	DDG (R)
	Sh. Ajay Negi	DDG (CHD)
	Sh. Sunil Bhat	AD (CHD)
BSNL	Sh. S.K. Chopra	PGM (NW-CM)
	Sh. Purushotam Lal	DGM
	Sh. Balvinder Kumar	AGM
BBNL	Sh. Jitender Setia	PGM (BN)
	Sh. Upender Pathak	DGM (BN)
COAI(Online)	Sh. Dhananjay Gawande	Director
	Sh. Deepak Gupta	Manager
DIPA(Online)	Sh. Greesh Kumar Tyagi	General Manager